MR. SPEAKER : May I suggest that the hon. Minister may please place it on the Table of the House and we may take it up on some other day.

श्री मधु लिमये : इसको फिर अगली बार लिया जाय।

MR. SPEAKER : He will place it on the Table of the House today. We shall take it up on some other day.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : After the Question Hour.

MR. SPEAKER : Not after the Question Hour. It will be within the Question Hour. We can have it on next Thursday.

FERTILIZER PLANT IN COOPERATIVE SECTOR

+

*93. SHRI BHOGENDRA JHA :
SHRI C. JANARDHANAN :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the scheme to set up a big fertilizer plant in the Co-operative sector in collaboration with the Co-operative League of America has been finalised;

(b) if so, the broad details thereof;

(c) the estimated cost thereof; and

(d) when the plant is likely to be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir.

(b) A letter of intent has been issued to M/s. Indian Farmers Fertilizer Co-operative Ltd., a fully Indian-owned concern, for the establishment of a fertilizer factory at Kandla. The project will have a capacity of 215,000 tonnes of nitrogen. 127,000 tonnes of P_2O_5 and 66,000 tonnes of K_2O.

(c) The preliminary estimate of cost is Rs. 89 25 crores, of which Rs. 38.17 crores is in foreign exchange; but this estimate is being reviewed.

(d) By 1971-72.

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, यह अमरीका के सहकारी संघ के साथ समझौता बातचीत जिस आधार पर चल रही है उसमें जितना अभी मंत्री महोदय ने बयान किया है उसके अलावा क्या और कोई शर्त है जिस तरीके की शर्त आमतौर से अमरीकी समझौते के साथ की जाती रही है या उसमें केवल उतनी ही बातें हैं जिनका कि ब्योरा उन्होंने दिया है और यह कि उसके प्रबन्धकों में कौन लोग होंगे ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : The Government of India felt that probably the figures are on the high side. So, we are examining it on our own. As regards other conditions, we have issued a letter of intent in favour of M/s. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. in which the various cooperatives in the following States have agreed to take part, namely, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Mysore, Madras and Orissa. So far as the foreign exchange portion is concerned, it will be by way of a loan and the only condition is that there will be an agreement between the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. and the Fertiliser Cooperative International Organisation whereby the selection of processes, engineering and construction, will be done with the assistance of the International Cooperative organisation. They will also be in management for a period until by mutual agreement, the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. can take it over. It will be based on indigenous naphtha. If there are any other particular questions to be asked, I will be happy to reply to them.

श्री भोगेन्द्र झा : जो इस प्रोजेक्ट के बारे में सिंहावलोकन हो रहा है और उसके बारे में उन्होंने दिया है उस सिंहावलोकन में उधर से अमरीकी सहकारी संघ से भी कोई मांग आई है या अपनी ओर से ही यह खर्च की कटौती करना भारत सरकार उसको जरूरी समझ रही है और इसके बारे में सिंहावलोकन हो रहा है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : So far as engineering, construction and technical

assistance are concerned, whatever resources are available in the country will be fully utilised. So far as distribution is concerned, the agreement is that they will be distributed to the cooperative societies which are taking equity participation in this. As far as the price control is concerned, there is to be no restriction on price control.

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि समझौता होगा भारत के जो यह कृषि सहकारी संगठन होंगे उन के बीच में और अमरीका के राष्ट्रीय सहकारी संघ के बीच में तो इस का मतलब यह हुआ कि समझौता अभी हुआ नहीं। अगर समझौता होना बाक़ी है अभी भी तो उस में क्या वे शर्तें भी हैं जो आमतौर से पहले आती रही हैं यानी उस खाद के दाम पर भारत सरकार कोई नियन्त्रण न रखे, भारत सरकार का कोई अधिकार न रहे। उस के वितरण पर भारत सरकार की कोई लगाम न रहे। जो आमतौर पर अमरीका के साथ समझौते होते हैं उस में पहली शर्त वह दी गई हैं दूसरे यह कि अमरीका का यह जो अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ है उस संघ के उधर के सदस्यगण कौन हैं और क्या वहां के भी खेती में हिस्सा लेने वाले लोग ही उस के संगठन में हैं या वहां उर्वरक कारखाने के जो मालिक लोग हैं उन का यह सहकारी संघ है? जो आमतौर से विदेशों में संघ के नाम पर जाते हैं और उर्वरक कारखाना खोलते हैं उस अमरीकी सहकारी संघ का चरित्र क्या है? दूसरे यह जो कारखाना कायम करने के बारे में हम सोच रहे हैं उस में विदेशी मुद्रा में वह चीजें भी शामिल हैं जो कि हमें भारत में ही उपलब्ध हो सकती हैं जिसकी कि वहां जरूरत नहीं पड़ेगी नाफ्ता के अलावा?

SHRI RAGHU RAMAIAH : As I said, there will be no control over the prices. The Government of India, initially, will have two-thirds share in equity participation. But gradually it will be left to the cooperatives to take over the entire equity share.

श्री भोगेन्द्र झा : मूल्य के नियन्त्रण पर कोई लगाम नहीं रहे तो यह उर्वरक किस भाव पर बिकेगा वह कौन तय करेगा? मंत्री महोदय के जवाब से यह बात साफ़ नहीं हुई उर्वरक का मूल्य निर्धारित होगा या नहीं उस पर नियन्त्रण रहेगा या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने बतला दिया है कि प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा बाक़ी शुरू में गवर्नमेंट आफ इंडिया का दो तिहाई हिस्सा इक्विटी पार्टिसिपेशन में रहेगा और धीरे धीरे सब गवर्नमेंट का होगा।

SHRI D. N. PATODIA : May I draw the attention of the hon. Minister to the recent statement by Dr. Sarabhai, the Chairman of the Atomic Energy Commission, stating that by use of atomic energy, the production of fertiliser, can be multiplied many-fold? May I know whether this particular process will be examined in this particular unit which is to be set up and, secondly, whether the scheme proposed by Tatas for the use of atomic energy has been taken into consideration?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : The answer to the first part of the question is "No". The answer to the second part of the question is that the Tata proposals are still under examination.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : May I know from which refinery in the western zone, the required amount of Naphtha will be supplied to the proposed plant?

SHRI ASOKA MEHTA : These details are still to be worked out.

MR. SPEAKER : The details are being worked out.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : When they have not worked out the details the amount of naphtha required for this plant, what is the use of proceeding with this?

SHRI ASOKA MEHTA : Before the proposal is finalised, all the details should be worked out fully. I am afraid I cannot give the information now.

श्री सरजू पाण्डेय : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि जो योजना विचाराधीन है उनमें उत्तर प्रदेश का भी नाम है। पिछली दफ़े एक प्रश्न के उत्तर में यह बतलाया गया था कि एक योजना उत्तर प्रदेश में भी अमरीकी कोआपरेटिव सोसाइटी के सहयोग से खोलने की योजना थी तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह योजना ड्रौप हो गई और वह एक ही कारखाना खुलेगा या वह उत्तर प्रदेश की योजना भी अभी उनके विचाराधीन है ?

श्री अशोक मेहता : इस वक्त एक ही कारखाना खुलेगा।

श्री सरजू पान्डेय : यू० पी० में भी एक कारखाना खुलने वाला था, उस का क्या हुआ ?

श्री अशोक मेहता : मैं ने जबाव दिया कि इस वक्त एक ही कारखाना खुलेगा और वह कांडला में खुलेगा।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : What is the percentage of capital participation in respect of different States ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : Punjab Rs. 2.5 crores; Haryana Rs. 1 crore; U.P. Rs. 2.5 crores; Gujarat Rs. 0.5 crore; Rajasthan Rs. 1 crore; Madhya Pradesh Rs. 0.5 crore; Maharashtra Rs. 0.5 crore; Andhra Pradesh 0.5 crore; Mysore 0.5 crore; Madras the same; and Orissa also the same.

SHRI S. S. KOTHARI : In view of the fact that the co-operative societies are reported not to be functioning properly and efficiently and there is an element of corruption in this sector, would the Government appoint a Commission of Inquiry to look into the whole co-operative movement and co-operative sector ? Secondly, how far does the Minister consider it safe to stake large amounts of public money in such projects ? When even the public sector is not able to deliver the goods properly, is the co-operative sector expected to do better ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : One of the important considerations in deciding on Kandla is that the co-operatives in Maharashtra, Gujarat, U.P. and so on are working satisfactorily and that would be a good base.

श्री रणधीर सिंह : जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिये खाद किसान के लिये जान है और देश में खाद की मांग बहुत ज्यादा है। खादी पैदावार भी दुगुनी और तिगुनी हो गई है, लेकिन किसान उस को खरीद नहीं सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सारे देश के किसानों की जो खाद की मांग है उस को कितने दिनों में पूरा किया जा सकेगा और कब तक किसानों को सब्सिडाइज्ड या कंसेशनल रेट पर खाद दी जा सकेगी ?

SHRI ASOKA MEHTA : The proposals which have reached a firm stage will give us a production capacity of 2.1 million tonnes by 1970-71. The other proposals which are under consideration, we hope, will give us a capacity of something over 3 million tonnes by 1971-72. We are confident that production from the plants, which have been firmly decided upon, by the end of the Fourth Plan will be of the order of 1.6 million tonnes.

श्री महाराज सिंह भारती : आज कांडला में जो नाइट्रोजन, P_2 और पोटाश जो सरकार बनाने जा रही है, क्या यह सच है कि उस के सम्बन्ध में पोटाश का कच्चा माल 100 फीसदी बाहर से आयेगा और फासफोरस का जो कच्चा माल है राक फास्फेट वह भी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उस का करोड़ों टन का भंडार होते हुए भी बाहर से ही मंगाया जायेगा, और नाइट्रोजन का जो नेप्था है वह भी चूंकि इस देश में उपलब्ध नहीं है उस कारखाने के लिये और फूड आयल सर्प्लस आप उस को दे नहीं सकेंगे, इसलिये वह भी बाहर से आयेगा। इन तीनों चीजों के बाहर से मंगाने के जो दाम होंगे वह भी उतने ही होंगे जितने कि खाद के बाहर से मंगाने के हैं, क्या यह भी सच है ?

श्री अशोक मेहता : यह गलत है ।

श्री महाराज सिंह भारती : कौन सी चीज गलत है ? जो कच्चे माल के दाम हैं वह उर्वरक के दाम के बराबर हैं यह गलत है या कि कच्चा माल बाहर से आयेगा यह गलत है ?

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य का आखिरी सवाल था कि कच्चे माल की कीमत क्या पक्के माल के बराबर होगी, मैंने कहा कि यह ठीक नहीं है ।

श्री महाराज सिंह भारती : उस से पहले भी एक सवाल था, उस का भी तो कुछ जवाब दिया जाना चाहिये । क्या यह तीनों चीजें इम्पोर्ट होंगी ?

MR. SPEAKER : He has replied that it is not true.

SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI : What is not true ?

MR. SPEAKER : Whatever you asked.

श्री मधु लिमये : क्या सब गलत है ?

SHRI ASOKA MEHTA : The question was this : we will be importing this and that and the cost of these imports will be the same as the cost of imported fertilisers; is that true ? That was the last question and I said that it was not true. If he wants to know what we will be importing and all that, these are matters which are being gone into. I cannot at this stage give all the details.

SHRI S. KUNDU : In order to have the balance in planning, it was suggested that some of the fertiliser plants should be put up in some of the less developed States and in this connection there was a proposal that a fertiliser plant would be put up at Paradeep Port. I would like to know how far this proposal has gone through.

Secondly, there is some proposal to put up nitrogen based fertilizer plant with naphtha as the main source of material. The production of naphtha is very small in the country and if these plants are put up, ultimately.....

MR. SPEAKER : This question has already been asked by Mr. Panigrahi and was answered. The Minister said that it is under examination. You are only repeating the same thing. If there are too many supplementaries, the result would be repetition of the same thing. Anyway, we may finish this question and then we shall go to the next question.

SHRI S. KUNDU : The amount of naphtha is very small....

MR. SPEAKER : He may sit down. The Minister is replying.

SHRI ASOKA MEHTA : Two questions have been asked. The first is whether any proposal is under consideration for setting up a plant at Paradeep. This matter is under consideration, but it has not reached that stage where I can make any kind of firm announcement.

Secondly, as far as the requirements of naphtha for fertiliser plants are concerned, this is being very carefully gone into. A number of considerations have to be gone into in order to reach certain conclusions. We have to have a projection of requirement of petroleum products in the country for the next five years and then from that we have to find out how much naphtha we will be able to produce. It is not easy for us to make a study of how the demand of other products of petroleum, the other oil products will go up in the next five years. We are assessing it as carefully as we can and then we are going to come to certain conclusions about naphtha. We hope that this study will be completed in the next four to six weeks. As soon as the results of the study are available and have been placed before the Government, I shall be happy to place the full information before the House.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : If I have heard the Minister correctly, he said that we have the majority shares, two-thirds, and we are getting only the foreign exchange by way of loan. May I know what prompted the Government to put the management of this fertiliser plant in the hands of the foreign collaborator ?

SHRI ASOKA MEHTA : That is because our co-operatives do not have the experience or the know-how, or the technical

competence either to organize the plant or to run it. For a certain period the training has to be given to them.

MASTER PLAN FOR DELHI

*95. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have received proposals to revise the Master Plan for Delhi;

(b) whether Government have received any communication about this from the Delhi Administration; and

(c) if so, the reactions of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No, but changes in the land use prescribed in the Master Plan for Delhi have been allowed, wherever they were found necessary, in accordance with the provisions of the Delhi Development Act, 1957.

(b) No.

(c) Does not arise.

श्री कंवरलाल गुप्त : दिल्ली में करीब 210 कालोनीज अनआथराइज्ड हैं और उन में 55 हजार प्लाट हैं। उन में से 30 हजार प्लाटों पर मकान बने हुए हैं जिन में 5 लाख आबादी रहती है। चूंकि उन में से अधिकांश मास्टर प्लान की ग्रीन बेल्ट में आते हैं, इस लिये वह रेगुलराइज नहीं हुए हैं। उन को नोटिसें दी जा रही हैं कि उन का डिमालिशन कर दिया जायेगा। इस का मतलब यह होगा कि कम से कम 7 या 8 करोड़ रुपया जो उन पर खर्च हुआ है वह वेस्ट हो जायेगा। क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे उन अनआथराइज्ड कालोनीज को रेगुलराइज करने के लिये क्या वह मास्टर प्लेन में कुछ परिवर्तन करेंगे ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो और जो 20 हजार प्लाट बाकी बचे हैं उन पर मकान बन जायें तथा आज तक जो उन के सिर पर तलवार लटक रही वह दूर हो जाये ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक अनआथराइज्ड कालोनीज का ताल्लुक है, मास्टर प्लान को रिवाइज करने का अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अनआथराइज्ड कालोनीज को किस प्रकार रेगुलराइज किया जा सकता है, इस के लिये हम ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन से कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट दे और बतलाये कि कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं, हर एक कालोनी में कौन सी जगह रेगुलराइज हो सकती है और कौनसी नहीं। उस के बाद फिर हम देखेंगे उस में क्या कुछ तब्दीली करने की जरूरत है।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि 50 हजार प्लाट हैं, उन में से 30 हजार तो बने हुये हैं, 20 हजार प्लाट बाकी बचते हैं। यह भी कहा गया है कि जिस जगह पर अनआथराइज्ड कालोनीज हैं उन में से कौन सी रेजिडेंशल हैं और कौन सी नान-रेजिडेंशल, उस को भी देखें। वह इस को देखेंगे। देखने के बाद जब वह गवर्नमेंट को बतलायेंगे तभी हम सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। यह आज नहीं बतलाया जा सकता कि हम को क्या करना है।

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि जब यह मास्टर प्लान बनाया गया था, तो यह अन्दाज़ा लगाया गया था कि दिल्ली की आबादी हर साल लगभग एक लाख के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन उस के मुकाबले में मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की आबादी डेढ़ और दो लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, जिस की वजह से सब कैलकुलेशन ग़लत साबित हो रहा है और यहां की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खत्म हो रही है। होम मिनिस्टर साहब ने इस बारे में जो कमेटी बनाई थी, मंत्री महोदय खुद भी उस में हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह रीकमेंडेशन दी है कि मास्टर प्लान को रिवाइज किया जाये। मंत्री महोदय कहते हैं कि मास्टर प्लान को रिवाइज करने की